I J C R M
International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Research Article

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण पद्धतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण

Dr. Sharwan Kumar
Lecturer, District Institute of Education and Training (DIET), Pirouta, Bhojpur, Bihar Education Service (B.E.S.)

Corresponding Author: *Dr. Sharwan Kumar

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18359466

सारांश

यह शोध पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP 2020) के परिप्रेक्ष्य में बिहार की उच्च शिक्षा प्रणाली में प्रचलित शिक्षण पद्धतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भारत में उच्च शिक्षा वर्तमान समय में परिवर्तनशील दौर से गुजर रही है, जबकि बिहार अभी भी सीमित संसाधन, शिक्षक-प्रधान और व्याख्यान-आधारित शिक्षण मॉडल पर अत्यधिक निर्भर है। पारंपरिक पद्धतियों के कारण छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन, समस्या-समाधान क्षमता, रचनात्मकता और व्यावहारिक अनुभव का विकास बाधित होता राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP 2020) अनुभवात्मक, बहु-विषयी और छात्र-केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जो आधुनिक वैश्विक अपेक्षाओं के अनुरूप है। किंतु बिहार में इस नए प्रतिमान के कार्यान्वयन में संरचनात्मक कमियाँ (जैसे अवसंरचना की कमी, डिजिटल असमानता, शिक्षक छात्र अनुपात में कमी), नीतिगत चुनौतियाँ तथा संस्थागत जड़ता प्रमुख बाधाएँ बनती हैं। सैद्धांतिक ढाँचों—निर्माणवाद, आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्र और ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण—के आधार पर विश्लेषण दिखाता है कि बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP 2020) के शिक्षण मॉडल की व्यवहार्यता कई सामाजिक–आर्थिक और प्रशासनिक बाधाओं से प्रभावित होती है। यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बिहार की उच्च शिक्षा प्रणाली में प्रभावी सुधार तभी संभव है जब शिक्षण पद्धतियों में मूलभूत परिवर्तन, शिक्षक क्षमता-विकास, डिजिटल अवसंरचना विस्तार और सामाजिक न्याय आधारित नीतियों को प्राथमिकता दी जाए।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 10-11-2025
- **Accepted:** 29-12-2025
- **Published:** 24-01-2026
- **IJCRM:**5(1); 2026: 218-224
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

Kumar S. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण पद्धतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(1):218-224.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मूल शब्द: राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP 2020), बिहार उच्च शिक्षा, शिक्षण पद्धतियाँ, निर्माणवाद, आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्र, छात्र-केंद्रित अधिगम, डिजिटल असमानता और बहु-विषयी शिक्षा

1. प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि और संदर्भ

भारत में उच्च शिक्षा का क्षेत्र पिछले कुछ दशकों में विस्तार तो देखा है, परंतु गुणवत्ता, पहुंच एवं समावेशन की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण तथा कौशल-आधारित रोजगार की बढ़ती मांग ने इस पुनर्गठन की आवश्यकता को और प्रबल बनाया है (Agarwal, 2020)। राष्ट्रीय स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (GER) 2021-22 में 28.4% हो गया है, जो 2014-15 के 23.7% से अधिक है, जिससे कुल नामांकन लगभग 4.33 करोड़ तक पहुँच गया है (Ministry of Education, 2023)। यह वृद्धि राष्ट्रीय शिक्षा नीति

© 2026 Dr. Sharwan Kumar. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

(NEP) 2020 के लक्ष्य से प्रेरित है, जो 2035 तक GER को 50% तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखती है।

किंतु, बिहार का परिदृश्य राष्ट्रीय औसत से स्पष्ट रूप से पीछे है। राज्य का GER 2021-22 में मात्र 17.1% रहा, जो राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है (Ministry of Education, 2023; Times of India, 2024)। बिहार के उच्च शिक्षा संस्थान संसाधनों की गंभीर कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव, पुरानी व्याख्यान-आधारित पद्धतियों पर निर्भरता, शोध संस्कृति की सीमितता तथा डिजिटल अवसंरचना के अभाव जैसी जटिल चुनौतियों से जूझ रहे हैं (Kumar & Sinha, 2021; Wikipedia, 2025)। ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यह स्थिति और भी विकट है, जहाँ बुनियादी तकनीकी संसाधनों तथा आधुनिक शिक्षण सुविधाओं का गंभीर अभाव है (Education for All in India, 2024)। ऐसे में, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP 2020)* द्वारा प्रस्तावित अनुभवात्मक, बहु-विषयक, कौशल-केंद्रित एवं छात्र-केंद्रित शिक्षण का प्रगतिशील ढाँचा (Ministry of Education, 2020) एक परिवर्तनकारी अवसर प्रस्तुत करता है।

1.2. समस्या का कथन

बिहार के उच्च शिक्षा संस्थानों में अभी भी पारंपरिक शिक्षण पद्धतियाँ—रटंत अधिगम (rote learning), शिक्षक-केंद्रित व्याख्यान (teacher-centric lectures) तथा अंक-उन्मुख मूल्यांकन—ही प्रमुखता से प्रचलित हैं। ये पद्धतियाँ छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन, समस्या-समाधान क्षमता, रचनात्मकता एवं जीवन कौशल के विकास में बाधक हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्नातक स्तर तक, अक्सर समय और बाजार की मांगों के अनुरूप तैयार नहीं हो पाते। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP 2020)* द्वारा अनुशंसित सहभागी, अनुभवात्मक एवं बहु-विषयक शिक्षण प्रतिमानों को बिहार की वर्तमान संरचनात्मक कमजोरियों, संसाधन अभाव तथा संस्थागत जड़ता के कारण प्रभावी ढंग से लागू करना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है, जिससे पारंपरिक मॉडल से आधुनिक मॉडल की ओर संक्रमण धीमा एवं असंतोषजनक बना हुआ है। इसलिए शोधकर्ता ने शीर्षक: "राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण पद्धतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण" का चयन किया है।

1.3 मुख्य शोध प्रश्न

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP 2020) द्वारा प्रस्तावित शिक्षण-अधिगम प्रतिमान बिहार की उच्च शिक्षा प्रणाली में किस सीमा तक लागू हो पा रहे हैं, और उनके प्रभावी कार्यान्वयन में कौन-कौन सी संरचनात्मक, संस्थागत एवं सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ प्रमुख भूमिका निभा रही हैं?

1.4 सहायक शोध प्रश्न (Subsidiary Research Questions)

- बिहार की उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रचलित पारंपरिक, शिक्षक-केंद्रित एवं रटंत-प्रधान शिक्षण पद्धतियों की प्रमुख विशेषताएँ, सीमाएँ तथा उनका छात्रों की अधिगम प्रक्रिया, कौशल-विकास और आलोचनात्मक चिंतन पर प्रभाव क्या है?
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP 2020) द्वारा प्रस्तावित छात्र-केंद्रित, अनुभवात्मक एवं बहु-विषयक शिक्षण दृष्टिकोण के सैद्धांतिक आधार (निर्माणवाद, आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्र एवं ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण) क्या हैं, और ये बिहार की वर्तमान शैक्षिक वास्तविकताओं से किस सीमा तक मेल खाते हैं?
- बिहार के उच्च शिक्षा संस्थानों में संसाधन-अभाव, शिक्षक संकट, डिजिटल विभाजन एवं संस्थागत जड़ता किस प्रकार NEP 2020 के शिक्षण मॉडल के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं, तथा इन बाधाओं का उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और समावेशिता पर क्या प्रभाव पड़ता है?

1.5. शोध के उद्देश्य (Objectives of the Study)

- बिहार की उच्च शिक्षा संस्थाओं में वर्तमान में प्रचलित पारंपरिक, शिक्षक-केंद्रित एवं रटंत-प्रधान शिक्षण पद्धतियों की प्रकृति, विशेषताओं एवं सीमाओं का विश्लेषण करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP 2020) द्वारा प्रस्तावित छात्र-केंद्रित, अनुभवात्मक एवं बहु-विषयक शिक्षण दृष्टिकोण के प्रमुख सैद्धांतिक आधारों का मूल्यांकन करना।
- बिहार के उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP 2020) के शिक्षण मॉडल के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख संरचनात्मक, संस्थागत एवं नीतिगत बाधाओं की पहचान एवं आलोचनात्मक समीक्षा करना।
- NEP 2020 के आदर्श शिक्षण प्रतिमान और बिहार की जमीनी शैक्षिक वास्तविकताओं के बीच विद्यमान अंतराल (gaps) का विश्लेषण का आकलन करना।
- उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं समावेशिता में सुधार हेतु संदर्भ-विशिष्ट, सैद्धांतिक एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

2. साहित्य समीक्षा

यह खंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) में शिक्षण पद्धतियों के प्रावधानों, उच्च शिक्षा के प्रमुख सैद्धांतिक ढांचों तथा बिहार के उच्च शिक्षा परिदृश्य पर मौजूदा साहित्य के समाकलन एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित है। यह समीक्षा इस शोध के लिए एक सैद्धांतिक आधार तैयार करती है।

2.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) में शिक्षण-अधिगम पद्धतियों के प्रमुख प्रावधान

मौजूदा साहित्य स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण पद्धतियों के एक मूलभूत परिवर्तन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करती है। यह नीति लंबे समय से प्रचलित व्याख्यान-आधारित, शिक्षक-केंद्रित एवं रटंत-प्रधान (rote learning) पद्धतियों की सीमाओं को स्वीकार करते हुए एक वैकल्पिक प्रतिमान का प्रस्ताव करती है (Kumar, 2019; Ministry of Human Resource Development, 2020)। इस नए प्रतिमान के केंद्र में अनुभवात्मक (experiential), खोजपूर्ण (inquiry-based), बहु-विषयक (multidisciplinary) तथा शिक्षार्थी-केंद्रित (learner-centric) शिक्षण को रखा गया है।

साहित्य में इस बात पर जोर दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) का उद्देश्य शिक्षण को निम्न-स्तरीय स्मरण (remembering) से हटाकर उच्च-स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों—जैसे आलोचनात्मक चिंतन (critical thinking), रचनात्मकता (creativity), समस्या-समाधान (problem solving) तथा नवाचार (innovation)—के विकास की ओर निर्देशित करना है (Schunk, 2020; Ministry of Education, 2020)। इस हेतु, नीति दस्तावेज़ परियोजना-आधारित अधिगम (project-based learning), शोध-आधारित अधिगम (research-based learning), इंटर्नशिप तथा

© 2026 Dr. Sharwan Kumar. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

स्थानीय संदर्भ-आधारित शिक्षण रणनीतियों को प्रोत्साहित करता है। बहु-विषयक दृष्टिकोण को अपनाने का निर्देश इस विश्वास से उपजा है कि वास्तविक जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान एकल विषयक ज्ञान से संभव नहीं है (MoE, 2020)।

2.2 उच्च शिक्षा में शिक्षण पद्धति के प्रमुख सैद्धांतिक ढांचे

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक बदलाव कई प्रमुख शैक्षणिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी पुष्टि मौजूदा साहित्य से होती है।

- **निर्माणवाद (Constructivism):** पियाजे (Piaget) के संज्ञानात्मक निर्माणवाद तथा वायगोत्स्की (Vygotsky) के सामाजिक निर्माणवाद के अनुसार, ज्ञान शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय रूप से एवं सामाजिक अंतर्क्रिया के माध्यम से निर्मित होता है (Schunk, 2020; Vygotsky, 1978)। वायगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित 'समीपस्थ विकास का क्षेत्र' (Zone of Proximal Development - ZPD) और 'पाड़-निर्माण' (scaffolding) की अवधारणाएँ NEP 2020 में शिक्षक की भूमिका को एक सूचना-प्रदाता से एक सुविधाकर्ता (facilitator) के रूप में बदलने के दृष्टिकोण से सुसंगत हैं।
- **आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्र (Critical Pedagogy):** पाउलो फ्रेरे (Paulo Freire, 1970) के इस सिद्धांत के अनुसार, शिक्षा एक मुक्ति का प्रक्रिया है, जो 'बैंकिंग मॉडल' (जहाँ ज्ञान जमा कराया जाता है) के स्थान पर 'संवादात्मक अधिगम' (dialogical learning) पर बल देती है। यह सिद्धांत NEP 2020 द्वारा रटंत अधिगम के विरोध तथा आलोचनात्मक चेतना (critical consciousness) विकसित करने के लक्ष्य के अनुरूप है।
- **ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण एवं क्षमता-आधारित शिक्षा:** एंडरसन एवं क्रैथवोहल (Anderson & Krathwohl, 2001) द्वारा संशोधित ब्लूम के वर्गीकरण में 'सृजन (creating)' एवं 'मूल्यांकन (evaluating)' जैसे उच्च-स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों को प्राथमिकता दी गई है। यह ढांचा क्षमता-आधारित शिक्षा (Competency-Based Education - CBE) से जुड़ता है, जिस पर NEP 2020 का जोर है। इसमें शिक्षण एवं मूल्यांकन का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि छात्रों में विशिष्ट, प्रदर्शन-योग्य क्षमताओं (competencies) का विकास करना है।

2.3 बिहार के उच्च शिक्षा परिदृश्य पर पूर्व अध्ययन एवं शोध अंतराल

बिहार के संदर्भ में उपलब्ध साहित्य एक ऐसी उच्च शिक्षा प्रणाली का चित्रण करता है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) के आदर्शों एवं वास्तविक कार्यान्वयन के बीच एक गहरी खाई को प्रदर्शित करती है।

- **पुरातन पद्धतियाँ, संसाधन अभाव एवं संरचनात्मक चुनौतियाँ:** अधिकांश अध्ययन इस बात पर एकमत हैं कि बिहार के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में व्याख्यान-केंद्रित (lecture-based) एवं शिक्षक-प्रभुत्वशाली (teacher-dominated) पद्धतियाँ ही प्रमुख हैं, जिससे छात्रों की सक्रिय सहभागिता सीमित रह जाती है (Agarwal, 2021; Kumar, 2019)। इसकी पृष्ठभूमि में अनेक संरचनात्मक बाधाएँ काम कर रही हैं:

(क) शिक्षकों की भारी कमी एवं मौजूदा शिक्षकों के लिए नवीन शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभाव (Education for All in India, 2025; Wikipedia, 2025) ।

(ख) बुनियादी ढांचे का गंभीर संकट, जिसमें आधुनिक प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कंप्यूटर एवं विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी शामिल है (Kumar & Sinha, 2021) । **(ग) एक सुदृढ़ डिजिटल अवसंरचना के अभाव में उत्पन्न डिजिटल विभाजन, विशेषकर ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।

- **NEP 2020 के संदर्भ में बिहार-विशिष्ट शोध अंतराल:** साहित्य समीक्षा से दो प्रमुख अंतराल सामने आते हैं। प्रथम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) के बहु-विषयक, अनुभवात्मक मॉडल को बिहार की विशिष्ट संसाधन समस्याओं एवं संस्थागत जड़ता (institutional inertia) के परिप्रेक्ष्य में कैसे लागू किया जाए, इस पर विस्तृत, संदर्भ-विशिष्ट रणनीतिक अनुसंधान का अभाव है। द्वितीय, हालांकि कुछ अध्ययन (जैसे Kulal et al., 2024) NEP के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों की ओर संकेत करते हैं, किंतु बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) अनुरूप शैक्षणिक पद्धतियों के प्रयोग एवं उनकी प्रभावकारिता का आकलन करने वाले व्यवस्थित अनुभवजन्य अध्ययन (systematic empirical studies) बहुत सीमित हैं।

3. बिहार में उच्च शिक्षा की शिक्षण पद्धतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण

यह खंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) के परिप्रेक्ष्य में बिहार के उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रचलित शिक्षण पद्धतियों की एक सैद्धांतिक आलोचनात्मक जांच प्रस्तुत करता है। यह विश्लेषण मौजूदा पारंपरिक पद्धतियों की विशेषताओं एवं सीमाओं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) के आदर्श प्रतिमान से उनकी तुलना, कार्यान्वयन बाधाओं तथा प्रमुख शैक्षिक सिद्धांतों के आलोक में उनकी व्यवहार्यता पर केंद्रित है।

3.1 पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों की विशेषताएँ, सीमाएँ एवं संदर्भ-विशिष्ट चुनौतियाँ

बिहार की उच्च शिक्षा में ऐतिहासिक रूप से पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों का व्यापक प्रभाव रहा है। अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि अधिकांश महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में व्याख्यान-आधारित (lecture-based), स्मृति-केन्द्रित (memory-oriented) तथा शिक्षक-प्रधान (teacher-centric) रणनीतियों का वर्चस्व बना हुआ है (Kumar, 2019; Agarwal, 2021)। इनकी मुख्य विशेषताएँ एकतरफा संप्रेषण (one-way communication), शिक्षक का नियंत्रण, पुस्तकीय ज्ञान पर अत्यधिक निर्भरता, सीमित संवाद एवं वास्तविक जीवन अनुभवों तथा प्रोजेक्ट कार्य का अभाव हैं।

इन पद्धतियों की प्रमुख सैद्धांतिक सीमाएँ हैं: (1) छात्रों में रचनात्मकता एवं आलोचनात्मक चिंतन का अभाव; (2) छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय भूमिका, जिससे सक्रिय भागीदारी कम होती है; (3) समस्या-समाधान कौशल का विकास बाधित होना; तथा (4) ज्ञान का अनुप्रयोगात्मक स्वरूप विकसित न हो पाना। बिहार के विशिष्ट संदर्भ में, ये सैद्धांतिक सीमाएँ अनेक गंभीर व्यावहारिक चुनौतियों से

© 2026 Dr. Sharwan Kumar. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

और जटिल हो जाती हैं (Wikipedia, 2025; Education for All in India, 2025):

- **शिक्षक अनुपस्थिति (Teacher Absenteeism) एवं कमी:** उच्च शिक्षा में नियमित शिक्षकों की भारी कमी एक गंभीर संकट है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, कई राजकीय विश्वविद्यालय सैकड़ों की संख्या में रिक्त पदों से जूझ रहे हैं, जिससे शिक्षण की निरंतरता एवं गुणवत्ता प्रभावित होती है (Times of India, 2025)। अस्थायी नियुक्तियाँ इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हैं।
- **पेशेवर विकास एवं प्रशिक्षण का अभाव:** शिक्षकों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) द्वारा अनुशंसित अनुभवात्मक शिक्षण (experiential learning) जैसी आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का प्रशिक्षण अपर्याप्त है। सतत पेशेवर विकास कार्यक्रमों के अभाव में शैक्षणिक नवाचार बाधित होता है।
- **सामाजिक-आर्थिक पूर्वाग्रह (Bias):** अध्ययनों से पता चलता है कि शैक्षणिक वातावरण में जाति-आधारित पूर्वाग्रह देखे गए हैं, जहाँ SC/ST/OBC समुदाय के छात्रों की क्षमताओं को कम आँका जाता है, जिससे समावेशी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होती है (Pandey & Kumar, 2025)।

3.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) के आदर्श प्रतिमान से तुलनात्मक विश्लेषण

NEP 2020 उच्च शिक्षा में एक क्रांतिकारी पद्धतिगत परिवर्तन का आह्वान करती है, जो बिहार की वर्तमान स्थिति से स्पष्ट अंतर रखती है (Ministry of Education, 2020; Ministry of Human Resource Development, 2020)।

- **छात्र-केंद्रित बनाम शिक्षक-केंद्रित (Student-centric vs. Teacher-centric):** NEP 2020 शिक्षार्थी को सक्रिय केंद्र में रखते हुए वैयक्तिक अधिगम (personalized learning) एवं खोजपूर्ण अधिगम (inquiry-based learning) पर बल देती है। इसके विपरीत, बिहार की प्रणाली अभी भी शिक्षक-प्रधान व्याख्यानों पर केंद्रित है, जहाँ छात्र मुख्यतः निष्क्रिय श्रोता की भूमिका में रहते हैं।
- **अनुभवात्मक व बहु-विषयक बनाम कठोर व विषय-विशिष्ट (Experiential & Multidisciplinary vs. Rigid & Discipline-specific):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) अनुभवात्मक (experiential), कौशल-आधारित (skills-based) और बहु-विषयक (multidisciplinary) शिक्षा को बढ़ावा देती है, जिसमें इंटर्नशिप, परियोजना कार्य एवं सामुदायिक अधिगम शामिल हैं। बिहार की उच्च शिक्षा, इसके विपरीत, एक कठोर, विषय-केन्द्रित संरचना में सिमटी हुई है, जहाँ व्यावहारिक अनुप्रयोग एवं विषयों के अंतर्संबंधों पर ध्यान देना सीमित है। इससे छात्रों में उच्च-स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों का विकास अवरुद्ध होता है।

3.3 बिहार में NEP 2020 के कार्यान्वयन की संरचनात्मक एवं नीतिगत बाधाएँ

NEP 2020 के शिक्षण मॉडल को बिहार में लागू करने का मार्ग अनेक गहन संरचनात्मक एवं नीतिगत चुनौतियों से अवरुद्ध है (Kulal et al., 2024)।

- **अवसंरचनात्मक कमी (Infrastructure Deficit):** ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कंप्यूटर, विश्वसनीय इंटरनेट, आधुनिक प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों एवं स्मार्ट कक्षाओं की गंभीर कमी है। यह घाटा अनुभवात्मक एवं डिजिटल-समृद्ध शिक्षण को एक दूर का सपना बना देता है।
- **डिजिटल विभाजन (Digital Divide):** शहरी-ग्रामीण असमानता गहरी है। ग्रामीण छात्रों के पास अक्सर उपकरणों (डिवाइस) तथा सस्ती इंटरनेट पहुँच का अभाव होता है, जिससे DIKSHA जैसे राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्मों तक उनकी पहुँच सीमित रह जाती है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) के मिश्रित अधिगम (blended learning) के लक्ष्यों के लिए एक बड़ी बाधा है।
- **संस्थागत जड़ता एवं शासन संबंधी मुद्दे (Institutional Inertia & Governance Issues):** परिवर्तन के प्रति संस्थागत प्रतिरोध, जटिल नौकरशाही प्रक्रियाएँ तथा नीतिगत कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त एवं समयबद्ध वित्तीय संसाधनों का अभाव नवीन शैक्षणिक पद्धतियों के समावेशन की गति को धीमा कर देते हैं।

3.4 सैद्धांतिक आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य

बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) के शिक्षण दृष्टिकोण की व्यवहार्यता का मूल्यांकन प्रमुख शैक्षिक सिद्धांतों के आलोक में किया जा सकता है।

- **निर्माणवादी सिद्धांत (Constructivist Theory) के आधार पर आलोचना:** निर्माणवाद के अनुसार, सीखना सक्रिय भागीदारी, अनुभव एवं सामाजिक अंतःक्रिया (वायगोत्स्की का ZPD एवं पाड़-निर्माण) पर आधारित है (Schunk, 2020; Vygotsky, 1978)। इस दृष्टि से, बिहार की प्रचलित शिक्षक-प्रधान, रटंत-आधारित पद्धति निर्माणवादी ढाँचे के मूलभूत विरोध में है। संसाधनों की कमी एवं शिक्षक अभाव के कारण, वह "पाड़-निर्माण" (scaffolding) प्रदान करना असंभव बना देती है, जो छात्रों को उनके समीपस्थ विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करती है। इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) का अनुभवात्मक दृष्टिकोण, जो निर्माणवाद पर आधारित है, बिहार की वर्तमान वास्तविकताओं में एक सैद्धांतिक आदर्श बनकर रह जाता है।
- **समता, समावेशन एवं सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से विश्लेषण:** फ्रेरे (1970) के आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्र के अनुसार, शिक्षा को दमन-रोधी एवं सामाजिक न्यायपरक होना चाहिए। बिहार के संदर्भ में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) की समावेशिता की प्रतिज्ञा कई स्तरों पर चुनौती का सामना करती है। सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ, जातिगत पूर्वाग्रह, तथा गहरा डिजिटल व संसाधन विभाजन मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहाँ पिछड़े वर्गों (SC/ST/OBC) एवं ग्रामीण छात्रों के लिए बहु-विषयक एवं व्यावहारिक अनुभवों तक पहुँच दुर्लभ है। नीति के आदर्शवादी लक्ष्य, संसाधन-आधारित असमानता की कठोर जमीनी हकीकत के सामने, व्यवहार में अप्रभावी होने का जोखिम रखते हैं। सामाजिक न्याय की दृष्टि से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) का कार्यान्वयन केवल शैक्षणिक पद्धति बदलने तक सीमित नहीं, बल्कि इन

© 2026 Dr. Sharwan Kumar. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने का एक साधन बनना चाहिए।

4. चर्चा

4.1 प्रमुख निष्कर्षों का संश्लेषण एवं सैद्धांतिक निहितार्थ

यह सैद्धांतिक विश्लेषण स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) द्वारा प्रस्तावित छात्र-केंद्रित, अनुभवात्मक, बहु-विषयक एवं कौशल-आधारित शिक्षण का आदर्श प्रतिमान और बिहार की उच्च शिक्षा की वास्तविकता के बीच एक गहरी एवं चिंताजनक खाई है। बिहार के अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में अभी भी पारंपरिक, व्याख्यान-प्रधान, शिक्षक-केंद्रित एवं रटंत-आधारित पद्धतियों का वर्चस्व बना हुआ है (Kumar, 2019)। यह स्थिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) के उस मूलभूत दर्शन के सीधे विपरीत है जो शिक्षण को अधिक अनुभवात्मक (experiential), समग्र (holistic), एकीकृत (integrated), खोज-संचालित (inquiry-driven), खोज-उन्मुख (discovery-oriented), शिक्षार्थी-केंद्रित (learner-centred), चर्चा-आधारित (discussion-based), लचीला (flexible) और आनंददायक (enjoyable) बनाने पर बल देती है (Ministry of Human Resource Development, 2020)।

- **शिक्षक संकट**: NITI Aayog (2025) के अनुसार, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों (SPUs) में 40% से अधिक शिक्षक पद रिक्त हैं, जिससे छात्र-शिक्षक अनुपात 30:1 जैसे प्रतिकूल स्तरपर पहुँच गया है, जबकि अनुशंसित अनुपात 15:1 है। यह स्थिति NEP 2020 द्वारा 'प्रेरित, ऊर्जावान और सक्षम संकाय' (Motivated, Energized and Capable Faculty) बनाने के लक्ष्य के विपरीत है।
- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा**: NITI Aayog (2025) की रिपोर्ट बताती है कि केवल 10% SPUs के पास अच्छी तरह से सुसज्जित शोध सुविधाएँ हैं और मात्र 32% के पास पूरी तरह कार्यात्मक डिजिटल पुस्तकालय हैं। यह अवस्था अनुभवात्मक, शोध-आधारित और डिजिटल-समर्थित शिक्षण के लिए एक बड़ी बाधा है।
- **शिक्षक पेशेवर विकास की चुनौती**: राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 10 लाख शिक्षक पद रिक्त हैं और शिक्षक शिक्षा संस्थानों (TEIs) में 92% निजी संस्थानों का वर्चस्व है, जिससे गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं (Education for All in India, 2025)। ऐसे में, बिहार जैसे राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) के तहत एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) और निरंतर पेशेवर विकास (CPD) को प्रभावी ढंग से लागू करना एक जटिल कार्य है।

4.2 सैद्धांतिक निहितार्थ: यह अध्ययन दर्शाता है कि निर्माणवाद (Constructivism) और आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्र (Critical Pedagogy) जैसे प्रगतिशील सैद्धांतिक ढाँचे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) के दर्शन का आधार हैं, संसाधनों की गंभीर कमी और गहरी सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के सामने अव्यावहारिक प्रतीत होते हैं। शैक्षणिक सिद्धांतों को बिहार जैसे संदर्भों में लागू करने के लिए उन्हें संदर्भ-विशिष्ट (context-specific) बनाने, चरणबद्ध कार्यान्वयन (phased implementation) पर जोर देने और समता (equity) तथा समावेशन (inclusion) को केंद्रीय स्थान देने की आवश्यकता है।

4.3 व्यावहारिक सुझाव एवं नीतिगत सिफारिशें

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) के दृष्टिकोण को बिहार में साकार करने के लिए निम्नलिखित बहु-स्तरीय हस्तक्षेप आवश्यक हैं:

क्षेत्र	प्रमुख सिफारिशें	अपेक्षित परिणाम
शिक्षक क्षमता एवं भर्ती	1. NISHTHA व NPST जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों का निरंतर पेशेवर विकास।2. केंद्रीकृत भर्ती अभियान चलाकर रिक्त पदों को शीघ्र भरना (NITI Aayog, 2025)।3. अनुबंधित भर्ती के स्थान पर स्थायी नियुक्तियों को प्राथमिकता देना (Education for All in India, 2025)।	गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, बेहतर छात्र-शिक्षक अनुपात, शिक्षण में नवाचार।
अवसंरचना एवं डिजिटलीकरण	1. राज्य के शिक्षा बजट को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 6% तक ले जाना (NITI Aayog, 2025)।2. स्मार्ट कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और हाई-स्पीड इंटरनेट का उन्नयन।3. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) जैसी योजनाओं का लाभ सभी संस्थानों तक पहुँचाना।	डिजिटल विभाजन में कमी, अनुसंधान क्षमता में वृद्धि, शिक्षण संसाधनों तक सार्वभौमिक पहुँच।
पाठ्यक्रम एवं शासन	1. बहु-विषयक पाठ्यक्रमों का चरणबद्ध क्रियान्वयन।2. संस्थानों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना तथा प्रदर्शन-आधारित वित्तपोषण (PBF) मॉडल लागू करना (NITI Aayog, 2025)।3. उद्योग-शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना।	छात्रों की रोजगार योग्यता में सुधार, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता, संस्थागत दक्षता।
समता एवं समावेशन	1. सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) के छात्रों के लिए लक्षित छात्रवृत्ति एवं सहायता कार्यक्रम।2. शिक्षक भर्ती में संवैधानिक आरक्षण नीतियों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करना (Education for All in India, 2025)।	सभी वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच, समावेशी शैक्षणिक वातावरण।

4. 4 अध्ययन की सीमाएँ एवं भविष्य के शोध के लिए सुझाव

यह एक सैद्धांतिक (theoretical) विश्लेषण है, जिसमें बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राथमिक आँकड़ों (जैसे शिक्षक/छात्र सर्वेक्षण) का अभाव है। अतः, इन निष्कर्षों की अनुभवजन्य पुष्टि (empirical validation) भविष्य के शोध के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा है।

4.5 भविष्य के शोध के लिए सुझाव

- **अनुभवजन्य अध्ययन**: बिहार के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) अनुरूप शिक्षण पद्धतियों के प्रयोग, चुनौतियों और प्रभाव का आकलन करने वाले विस्तृत क्षेत्र अध्ययन।
- **तुलनात्मक विश्लेषण**: बिहार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) कार्यान्वयन में अग्रणी अन्य राज्यों (जैसे केरल, तमिलनाडु) की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन।
- **दीर्घकालिक प्रभाव आकलन**: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) के विभिन्न घटकों (जैसे बहु-विषयक शिक्षा, कौशल एकीकरण) का छात्र सीखने के परिणामों और रोजगार पर दीर्घकालिक प्रभाव का अध्ययन।

© 2026 Dr. Sharwan Kumar. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

5. निष्कर्ष

बिहार की उच्च शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) द्वारा निर्धारित प्रगतिशील, बहु-विषयक, छात्र-केंद्रित एवं कौशल-आधारित शिक्षण के आदर्श मानकों से वर्तमान में काफी दूर है। पारंपरिक, शिक्षक-केंद्रित पद्धतियों का वर्चस्व, 40% से अधिक शिक्षक पदों की रिक्तता, और डिजिटल एवं भौतिक अवसंरचना का अभाव मुख्य अवरोध हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) का सैद्धांतिक दृष्टिकोण, हालाँकि प्रशंसनीय है, बिहार की जमीनी वास्तविकताओं में संसाधन-आधारित असमानताओं और संस्थागत जड़ता के कारण अप्रभावी रहने का जोखिम रखता राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) के दृष्टिकोण को बिहार में सफलतापूर्वक साकार करने के लिए केवल नीतिगत दस्तावेज पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए एक समग्र, संसाधन-समृद्ध एवं चरणबद्ध रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षक भर्ती एवं क्षमता निर्माण, बुनियादी ढाँचे का व्यापक उन्नयन, डिजिटल समावेशन, संस्थागत स्वायत्तता में वृद्धि, और सामाजिक न्याय को केंद्र में रखते हुए समावेशी नीतियों का समन्वित क्रियान्वयन शामिल हो। बिहार जैसे राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार न केवल राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, बल्कि 2035 तक 50% GER के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी एक अनिवार्य शर्त है। यह समय आदर्श और यथार्थ के बीच की खाई को पाटने का है।

REFERENCES

1. Agarwal P. *Challenges and reforms in Indian higher education*. New Delhi: Academic Publications; 2020.
2. Agarwal R. Challenges in higher education in Bihar: A situational analysis. *J Educ Dev*. 2021;12(2):45–57.
3. Anderson LW, Krathwohl DR, editors. *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. New York: Longman; 2001.
4. Education for All in India. Trends and analysis of gross enrolment ratio (GER) in higher education in India [Internet]. 2024 [cited 2026 Jan 23]. Available from: https://educationforallinindia.com/trends-analysis-of-gross-enrolment-ratio-ger-in-higher-education-in-india-2024/
5. Education for All in India. Teacher capacity building: Progress, challenges, and pathways under NEP 2020 [Internet]. 2025 Aug 14 [cited 2026 Jan 23]. Available from: https://educationforallinindia.com/teacher-capacity-building-progress-challenges-and-pathways-under-nep-2020/
6. Freire P. *Pedagogy of the oppressed*. New York: Herder and Herder; 1970.
7. Kulal A, N A, Dinesh S, Bhat DC, Girish A. Evaluating the promise and pitfalls of India's National Education Policy 2020: Insights from the perspectives of students, teachers, and experts. *SAGE Open*. 2024;14(4). doi:10.1177/21582440241279367
8. Kumar R, Sinha P. Issues and opportunities in Bihar's higher education landscape. *J Indian Educ*. 2021;46(2):45–58.
9. Kumar S. Pedagogical practices in Bihar's colleges: A field study. *Indian J High Educ*. 2019;7(1):22–34.
10. Ministry of Education, Government of India. *National Education Policy 2020* [Internet]. 2020 [cited 2026 Jan 23]. Available from: https://www.education.gov.in
11. Ministry of Education, Government of India. *All India Survey on Higher Education (AISHE) 2021–22* [Internet]. 2023 [cited 2026 Jan 23]. Available from: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1999713
12. NITI Aayog. *Expanding quality higher education through states and state public universities*. New Delhi: Government of India; 2025.
13. Pandey A, Kumar A. Discrimination in educational institutions: A case study of Bihar. *J Soc Incl Stud*. 2025. doi:10.1177/2455328X211067603
14. Schunk DH. *Learning theories: An educational perspective*. 8th ed. New York: Pearson; 2020.
15. Times of India. Gross enrolment ratio in state increases to 17% [Internet]. 2024 Jan 28 [cited 2026 Jan 23]. Available from: https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/gross-enrolment-ratio-in-state-increases-to-17/articleshow/107196800.cms
16. Times of India. State public universities grappling with faculty shortages, poor infrastructure: NITI Aayog [Internet]. 2025 Feb 10 [cited 2026 Jan 23].

© 2026 Dr. Sharwan Kumar. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

17. Vygotsky LS. *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge (MA): Harvard University Press; 1978.
18. Wikipedia. Education in Bihar [Internet]. 2025 [cited 2026 Jan 23]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Bihar

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Author

डॉ. श्रवण कुमार पिछले सोलह वर्षों से शिक्षा जगत में विभिन्न अकादमिक भूमिकाओं में सक्रिय हैं। वर्तमान में वे बिहार शिक्षा सेवा के शोध एवं अध्यापन उपसंवर्ग में व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं। उनके शोध पत्र राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। उनकी रुचियाँ स्कूल नेतृत्व, शिक्षण-अधिगम, NEP-2020, डिजिटल साक्षरता और शैक्षिक नवाचार हैं।

© 2026 Dr. Sharwan Kumar. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/